



भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र: स्टार्ट अप के लिए सरकारी पहल और योजनाएं

डॉ. नमिता कोचर*, डॉ. समीर वर्मा[†]

*[†] सहायक प्रोफेसर, जीएनए विश्वविद्यालय, फगवाड़ा

आलेख जानकारी

प्राप्त: 19 दिसंबर, 2023

संशोधित: 16 फरवरी, 2024

प्रकाशित: 30 जून, 2024

संपादक: डॉ. रवि कांत

* अनुरूपी लेखक

Email: namita.kalra@gnauniversity.edu.in
9814577780

खुला एक्सेस

DOI:

यह क्रिएटिव कॉमन्स एट्रिब्यूशन लाइसेंस

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>) की शर्तों के तहत वितरित एक ओपन एक्सेस लेख है, जो किसी भी माध्यम में अप्रतिबंधित उपयोग, वितरण और पुनरुत्पादन की अनुमति देता है, बशर्ते मूल कार्य उचित रूप से उद्धृत किया गया है।



<https://vbh.rase.co.in/>

Copyright© DHE

सारांश

भारत एक विकासशील देश है। चूंकि यह दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, इसलिए यहाँ नौकरियों की माँग में वृद्धि हुई है। हालाँकि, सरकार द्वारा व्यवसाय-अनुकूल माहौल बनाने की पहल पर प्रतिदिन कई कार्यक्रम और नीतियाँ पेश की जा रही हैं। स्टार्टअप के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र इन पहलों में से एक है। एक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र व्यक्तियों, विकास के विभिन्न चरणों में स्टार्टअप और विभिन्न प्रकार के संगठनों से बना होता है जो नए स्टार्टअप व्यवसायों को बनाने और विकसित करने के लिए एक साथ काम करते हैं। स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का प्राथमिक लक्ष्य एक टीम के सदस्य के साथ मिलकर नई अवधारणाओं, खोजों, अध्ययनों और आविष्कारों को क्रियान्वित करना है। लक्ष्य एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जो स्टार्टअप उद्यमों के विस्तार का समर्थन करता है और प्रचुर मात्रा में रोजगार के अवसरों और निरंतर आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। इस प्रयास से, सरकार को स्टार्टअप में नवाचार और डिजाइन-आधारित विकास को बढ़ावा देने की उम्मीद है। भारत ने एक संपन्न स्टार्टअप वातावरण विकसित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है, जैसा कि नए व्यवसायों की तेज़ी से बढ़ती संख्या से देखा जा सकता है। संस्थापकों में से बहत्तर प्रतिशत 35 वर्ष से कम उम्र के हैं। युवा उद्यमियों के साथ भी, सामाजिक समस्याओं के लिए अभिनव समाधान लाने के लिए भारत दुनिया के शीर्ष पाँच देशों में से एक है। अमेरिका और चीन के बाद, भारत में दुनिया भर में स्टार्टअप एक्सेलेरेटर और इनक्यूबेटर की तीसरी सबसे बड़ी सांद्रता है। डेटा के अनुसार, 2016 और 2017 के बीच इनक्यूबेटर और स्टार्ट-अप में 40% की वृद्धि हुई। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, बैंक ऋण सुविधा योजना और एकल बिंदु पंजीकरण योजना कम से कम 50 क्षेत्र-विशिष्ट और क्षेत्र-अज्ञेय स्टार्टअप कार्यक्रमों में से कुछ हैं जिन्हें भारत सरकार ने लॉन्च किया है। भारत में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के प्रयास में, भारत सरकार ने "स्टार्ट-अप इंडिया" पहल शुरू की है। वर्तमान अध्ययन का प्राथमिक फोकस भारत में स्टार्टअप इको-सिस्टम का उदय और क्षमता है, साथ ही इस संबंध में सरकार की भागीदारी और गतिविधियाँ भी हैं। लुधियाना, जिसे पंजाब का मैनचेस्टर कहा जाता है, 100 से अधिक स्टार्ट-अप का घर है जिसे अध्ययन के लिए जनसंख्या के रूप में लिया गया है। स्टार्टअप से डेटा एकत्र करने के लिए संरचित प्रश्नावली का उपयोग किया गया था। प्राथमिक लक्ष्य यह पता लगाना है कि स्टार्ट-अप को भारत सरकार की योजनाओं के बारे में कितनी जानकारी है और दूसरा, इन स्टार्ट-अप ने क्या लाभ प्राप्त किए हैं, इसकी जांच करना। "स्टार्ट-अप इंडिया" और "मेक इन इंडिया" पहलों के तहत, सरकार ने कई कार्यक्रम बनाए हैं जो इस अध्ययन का विषय हैं। इन कार्यक्रमों में कच्चे माल के समर्थन कार्यक्रम, संधारणीय वित्त कार्यक्रम और कई अन्य शामिल हैं। यह देखा गया है कि उद्यमियों का एक अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा कुछ हद तक इस बात से अवगत है कि इस तरह की योजनाएँ मौजूद हैं, और प्राप्त लाभ उस कम अनुपात को दर्शाता है।

कूट शब्द: चालू होना पारिस्थितिकी तंत्र, सरकारी पहल, उद्यमिता, स्टार्ट-अप वित्तपोषण, सरकारी योजनाएँ।

परिचय

स्टार्टअप एक नवगठित कंपनी इकाई है, या जो बनने की प्रक्रिया में है। इस समय व्यवसाय मॉडल

बाजार, लक्षित उपभोक्ता, प्रदान की जाने वाली सेवाओं, व्यवसाय की शर्तों और शर्तों आदि के संबंध में प्रयोग करता है। स्टार्टअप ऐसे व्यवसाय हैं जो प्रयोगात्मक चरण में हैं और जिनके पास अभी तक एक अच्छी तरह से परिभाषित व्यवसाय मॉडल या परिभाषित उत्पाद-बाजार-ग्राहक संरचना नहीं है। यह वास्तव में एक संगठन की शुरुआत है। स्टार्टअप को अपने ब्रांड को पूरी तरह से परिभाषित करने के लिए समय चाहिए क्योंकि वे मुख्य रूप से नए व्यवसाय मॉडल विकसित करने पर केंद्रित हैं। अध्ययनों से पता चला है कि स्टार्टअप सामान्य उद्यमिता और रोजगार वृद्धि का समर्थन करते हैं। नौकरी सृजन के लिए बहुत सारे अवसर होंगे क्योंकि आज का स्टार्टअप कल के सफल निगम में विकसित होगा। स्टार्टअप को भविष्य के पथप्रदर्शक के रूप में संदर्भित किया जा सकता है क्योंकि वे बाजारों, उपभोक्ताओं और समाज के व्यवस्थित विश्लेषण पर आधारित हैं। स्टार्टअप ऐसी परियोजनाओं में शामिल होते हैं जो सामाजिक मुद्दों और इच्छाओं को संबोधित करती हैं। कम से कम संसाधनों के साथ शुरुआत करते हुए, स्टार्टअप बाज़ार में उपलब्ध नए उत्पादों या संसाधनों को पेश करके अपने व्यवसाय को बढ़ाते हैं। स्टार्टअप "हाथ में पक्षी" रणनीति अपनाते हैं, ऐसे व्यावसायिक विचारों का पीछा करते हैं जो जल्दी से लॉन्च हो जाते हैं और अतिरिक्त संसाधनों की बहुत कम आवश्यकता होती है। स्टार्टअप औसत व्यक्ति की आवश्यकताओं की पहचान करते हैं और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रचनात्मक तरीके अपनाते हैं। मूल्य वितरण प्रक्रिया के किसी भी बिंदु पर नवाचार हो सकते हैं। उत्पाद वितरण और डिजाइन चरणों के दौरान नवाचार हो सकता है। उद्यमी उपभोक्ता अपेक्षाओं और वस्तुओं और सेवाओं की पहुंच के बारे में बाजार में अंतराल का मूल्यांकन करते हैं। स्टार्टअप ग्राहक अपेक्षाओं को पूरा करने और उससे आगे बढ़ने के लिए उत्पाद और सेवा डिजाइन में अपने लचीलेपन का लाभ उठाते हैं। लोग स्टार्टअप इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं; विभिन्न चरणों में स्टार्टअप और एक स्थान पर विभिन्न संगठन नए स्टार्ट-अप उद्यमों को बनाने और बढ़ाने के लिए एक प्रणाली के रूप में एक साथ काम करते हैं। विश्वविद्यालय, वित्तीय एजेंसियाँ, सहायता समूह, शोध एजेंसियाँ, सेवा प्रदाता संगठन इत्यादि कुछ ऐसी श्रेणियाँ हैं जिनमें इन संगठनों को विभाजित किया जा सकता है। स्टार्ट-अप इकोसिस्टम का प्राथमिक लक्ष्य टीम के सदस्य के साथ मिलकर नई अवधारणाओं, खोजों, अध्ययनों और आविष्कारों को क्रियान्वित करना है। इसका लक्ष्य एक मजबूत इकोसिस्टम बनाना है जो स्टार्ट-अप उद्यमों के विस्तार का समर्थन करता है और प्रचुर मात्रा में रोजगार के अवसरों और निरंतर आर्थिक

विकास को बढ़ावा देता है। इस प्रयास से, सरकार को स्टार्ट-अप में नवाचार और डिज़ाइन-आधारित विकास को बढ़ावा देने की उम्मीद है। हर साल औसतन 3,100 नए स्टार्ट-अप और 800 से ज़्यादा अन्य स्टार्ट-अप देखे जाते हैं। भारत ने एक संपन्न स्टार्टअप वातावरण विकसित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है, जैसा कि नए व्यवसायों की तेज़ी से बढ़ती संख्या से देखा जा सकता है। इसके अलावा, बेहतर प्रतिशत संस्थापक 35 वर्ष से कम उम्र के हैं। युवा उद्यमियों के साथ भी, सामाजिक समस्याओं के लिए अभिनव समाधान लाने के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष पाँच देशों में से एक है। अमेरिका और चीन के बाद, भारत में दुनिया भर में स्टार्टअप इनक्यूबेटर और एक्सेलेरेटर की तीसरी सबसे बड़ी सांद्रता है। दरअसल, 2016 और 2017 के बीच इनक्यूबेटर और स्टार्ट-अप में 40% की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, बैंक ऋण सुविधा योजना और एकल बिंदु पंजीकरण योजना, कम से कम 50 क्षेत्र-विशिष्ट और क्षेत्र-विशिष्ट स्टार्टअप कार्यक्रमों में से कुछ हैं जिन्हें भारत सरकार ने लॉन्च किया है। "नए उद्यमों" के विकास का समर्थन करने वाले "पारिस्थितिकी तंत्र" स्थापित करने के लिए, दुनिया के अधिकांश गतिशील क्षेत्र मुख्य रूप से एक प्रो-स्टार्ट-अप वातावरण को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं (मैनज़ेला, 2015)। भारत को एक अद्वितीय उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाता है क्योंकि यह स्टार्ट-अप उद्भव और निकास दोनों के मामले में दुनिया के स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्रों में तीसरे स्थान पर है, जिसमें 2015 में लगभग पाँच बिलियन डॉलर का वित्तपोषण है। इसके अतिरिक्त, भारत में हर दिन तीन से चार नए स्टार्ट-अप स्थापित होते हैं (टाइम्स ऑफ़ इंडिया रिपोर्ट, 2015)। अनुमान है कि भारत में 4200 स्टार्ट-अप हैं, जो लगभग 85000 रोजगार के अवसर पैदा करते हैं (एग्री स्टार्ट-अप एक्सपो 2018)। अनुमान है कि 2020 तक लगभग 11500 स्टार्ट-अप होंगे, जिससे 2 से 3 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे (FICCI और Yes Bank Start-Up Report)। स्टार्ट-अप इकोसिस्टम ने वर्ष 2018 के साथ एक नए चरण में प्रवेश किया है। स्टार्ट-अप को सलाह देने के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा स्थापित करना इन समयों में अनिवार्य है। अर्थव्यवस्था के स्टार्टअप क्षेत्र के विकास का समर्थन करने के लिए सरकार, शैक्षणिक संस्थानों और व्यवसायों के बीच सहयोग आवश्यक है। निजी निवेश पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के अलावा, स्टार्टअप समुदाय को बढ़ावा देने के लिए सरकार की कई पहल और प्रोत्साहन भी महत्वपूर्ण हैं। डीआईपीपी की प्रमुख इन्वेस्ट इंडिया परियोजना के तहत, भारत सरकार ने जनवरी 2016 में स्टार्ट-अप इंडिया एक्शन प्लान पेश किया। सरकार के

प्रयास का उद्देश्य स्टार्टअप का समर्थन करना और उनके विकास और नवाचार को गति देना है। इसके अलावा, 14 सितंबर, 2016 को सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय पूंजी को लुभाने और भारतीय व्यवसायों को विनिर्माण उद्योग में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करने के लक्ष्य के साथ "मेड इन इंडिया" अभियान शुरू किया। स्टार्ट-अप में विश्वास पैदा करने के लिए, सरकार ने बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) की सुरक्षा बढ़ा दी और अधिकांश उद्योगों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा बढ़ा दी।

चालू होना भारत पहल

भारत सरकार ने देश में नवाचार और स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए स्टार्ट-अप इंडिया कार्यक्रम शुरू किया ताकि दीर्घकालिक आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकें। सरकार का लक्ष्य नवाचार और डिजाइन के माध्यम से स्टार्टअप को उनके विकास में सहायता करना है। 16 जनवरी, 2016 को, भारत सरकार ने इस परियोजना के लिए कार्य योजना का अनावरण किया, जिसमें स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के हर पहलू को शामिल किया गया है। इस अभियान के तहत, सरकार ने कई स्टार्टअप-अनुकूल कार्यक्रम शुरू किए हैं। स्टार्ट-अप इंडिया अभियान के परिणामस्वरूप स्टार्ट-अप इंडिया हब की स्थापना हुई, जिसने इनक्यूबेशन, वित्तीय सहायता, व्यवसाय योजना सहायता, पिचिंग सहायता और अन्य आवश्यकताओं के साथ लगभग 660 स्टार्ट-अप की सहायता की है। हब इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से स्टार्ट-अप से 1,14,000 से 1,44,000 तक की पूछताछ तक पहुँचने में सक्षम है। इसके अलावा, DIPP ने 14,036 स्टार्ट-अप अनुप्रयोगों की पहचान की है। अक्टूबर 2014 से, 22 राज्यों ने पहले ही स्टार्ट-अप नीतियाँ विकसित की हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गोवा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं (स्टार्ट-अप इंडिया रिपोर्ट 2018)। कॉर्पोरेट संगठनों के विभिन्न आकार और विन्यासों द्वारा स्टार्टअप के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र को भी सुगम बनाया जाता है। उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रों द्वारा आधुनिक व्यावसायिक उपक्रम शुरू किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए भारत ने हाल ही में एक-व्यक्ति कंपनियों और सीमित देयता भागीदारी की अनुमति दी है। जो देश सक्रिय रूप से स्टार्टअप का समर्थन करते हैं, उन्हें अपने सामान्य कारोबारी माहौल को लगातार बेहतर बनाना चाहिए।

उदाहरण के लिए, 2017 और 2018 के बीच, व्यापार करने में आसानी सूचकांक में भारत की स्थिति 100 से बढ़कर 77 हो गई। यह भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने की व्यापक योजनाओं के अनुरूप है। सरकारी तंत्र में समग्र रूप से सुधार से व्यवसाय से संबंधित लालफीताशाही में कमी आती है। स्टार्टअप के लिए एक मजबूत वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र आवश्यक है। एंजेल निवेशक, निजी इक्विटी फर्म, मित्र और परिवार स्टार्टअप को उनकी पहली पूंजी प्रदान करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र परिपक्व वित्तीय अभिनेताओं और संस्थानों की सहायता से स्थापित किया जाता है।

साहित्य की समीक्षा

दादजी और दादजी (2016) के अनुसार, ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से जी.वी.सी. द्वारा समर्थित अधिकांश स्टार्ट-अप विफल हो जाते हैं या निजी वी.सी. द्वारा प्रायोजित स्टार्ट-अप की तुलना में खराब प्रदर्शन करते हैं, जिसमें पक्षपातपूर्ण चयन प्रक्रिया और पारदर्शिता की कमी शामिल है। बटलर एट अल. (2014) के शोध के अनुसार, सरकारी नीतियों का नौकरियों और व्यवसायों के उद्भव और अस्तित्व पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। सभी बातों पर विचार करने पर, साक्ष्य ने सुझाव दिया कि मामूली सार्वजनिक नीतियाँ व्यवसाय मालिकों को कंपनी में प्रवेश करने में आने वाली कई तरह की बाधाओं को दूर करने और उनके उद्यमशीलता कौशल के वितरण को बढ़ाने में सहायता कर सकती हैं। चांगहोंग एट अल. (2016) ने पाया कि जब आर्थिक वृद्धि कम होने की तुलना में अधिक मजबूत थी, तो एंजेल निवेश पर सरकारी नीतियों के लाभकारी लाभ अधिक स्पष्ट थे। इसके अलावा, बड़ी एंजेल निवेश राशियों से मिलने वाले रिटर्न पर उन नीतियों का अधिक प्रभाव पड़ा जो उद्यमशीलता का समर्थन करती हैं, न कि छोटे निवेशों से मिलने वाले रिटर्न पर। एंजेल निवेशकों को अधिक प्रभावी निवेश करने के लिए ऐसी नीतियों द्वारा आकार दिया गया है और उनका मार्गदर्शन किया गया है। गुआन और यान (2015) के अनुसार, उद्यमों के अभिनव आर्थिक प्रदर्शन पर कर क्रेडिट और विशेष ऋण जैसे विशेष सरकारी वित्तीय प्रोत्साहनों का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह पाया गया कि सामान्य या उच्च तकनीक कंपनियों के पेटेंट से कोई सरकारी वित्तीय प्रोत्साहन जुड़ा नहीं था। कैसानोवा एट अल. (2017) के अनुसार, बाजार में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ऋण और इक्विटी पूंजी प्रदान करने वाले सरकारी कार्यक्रमों का वर्णन किया गया है। कई देशों ने अनुदान, ऋण वित्तपोषण या उद्यम पूंजी के माध्यम से स्टार्ट-अप व्यवसायों को वित्तपोषित करने की पहल की है। पाठक (1972) के अनुसार, उद्यमशीलता कौशल का विकास काफी हद तक कई तत्वों के कारण होता है, जिसमें

संपर्क, शिक्षा, वित्त, अनुकूल और समय पर सरकारी नीतियां और व्यवसायों की ओर से त्वरित लचीलापन शामिल हैं। राव (1986) के विश्लेषण के अनुसार, सरकारी नीतियों के परिणामस्वरूप आंध्र प्रदेश की व्यावसायिक शुरुआत निस्संदेह बढ़ी है। पिल्लई (1989) के अनुसार, केरल राज्य की राज्य सरकार की वित्तीय और विपणन सहायता, साथ ही सरकार द्वारा स्थापित प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षण, सभी ने क्षेत्र में महिला उद्यमियों के उत्थान में योगदान दिया। इसके अलावा, शारदादेवी (1989) का मानना है कि नए कार्यक्रम, विभाग और संस्थान, साथ ही सरकारी सहायता और संघीय और राज्य स्तर पर विभिन्न आधिकारिक और गैर-आधिकारिक संस्थाओं की स्थापना, सभी ने महिला उद्यमियों के उत्थान में महत्वपूर्ण रूप से सहायता की है। देशपांडे (1989) इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि राजनीतिक व्यवस्था और सरकारी नीतियां उद्यमिता के निर्माण को प्रभावित करती हैं; फिर भी, उनका मानना था कि सरकार सभी जातियों और धर्मों के व्यवसाय मालिकों का समर्थन करने में असमर्थ है। शर्मा और सिंह ने पाया कि व्यवसायिक पृष्ठभूमि वाले अधिकांश लोग सरकारी सेवाओं का उपयोग करते हैं। हालाँकि, जेम्स जे. बेमा (1960) का मानना था कि सरकार मध्यम आकार के व्यवसायों की अनदेखी करती है क्योंकि छोटे पैमाने के क्षेत्रों को विकासशील पहलों से अधिक ध्यान मिलता है। सिंह (1964) के अनुसार, किसी भी कंपनी ने अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए किसी सार्वजनिक या निजी संस्था से ऋण नहीं लिया है या सरकारी सहायता प्राप्त नहीं की है। उद्यमशील उपक्रमों के निर्माण पर सरकारी सब्सिडी और प्रोत्साहन का प्रभाव व्यापक जांच का विषय रहा है। हालाँकि, साहित्य ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि उद्यमियों को सरकारी सहायता प्रणाली में कम प्रतिनिधित्व क्यों दिया जाता है, या उन्हें सरकार की सब्सिडी और कार्यक्रमों के बारे में पता है या नहीं। इसके अलावा, पंजाब, विशेष रूप से लुधियाना के अध्ययन पर सीमित साहित्य है जिसे अपने बेहतरीन होजरी उत्पादों के कारण पंजाब का मैनचेस्टर कहा जाता है। यह वर्तमान जांच को आगे बढ़ाने के लिए रूपरेखा प्रदान करता है, जिसके निम्नलिखित लक्ष्य हैं:

उद्देश्य

1. भारत में स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व की जांच करना।
2. भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के विकास और भविष्य की संभावनाओं में सरकार की पहल और भूमिका का अध्ययन करना।
3. स्टार्ट-अप के लिए सरकारी कार्यक्रमों के बारे में लुधियाना के

लोगों में जागरूकता के स्तर की जांच करना।

4. यह आकलन करना कि लुधियाना के स्टार्ट-अप किस हद तक सरकारी योजनाओं का उपयोग कर रहे हैं।

शोध पद्धति

अध्ययन का नमूना आकार 100 था और अध्ययन की जनसंख्या लुधियाना थी। स्टार्ट-अप के लिए सरकारी पहल और योजनाओं के बारे में लोगों की जागरूकता के स्तर तक पहुँचने के लिए उद्यमियों से जानकारी एकत्र करने के लिए एक संरचित प्रश्नावली का उपयोग किया गया था। अध्ययन के तहत इस्तेमाल की गई सांख्यिकीय तकनीकें भारित औसत, तुलनात्मक माध्य और ची स्क्रायर परीक्षण थीं।

अध्ययन की परिकल्पना

- H0: आयु के आधार पर जागरूकता के स्तर में कोई अंतर नहीं है।
- H1: लिंग के आधार पर जागरूकता के स्तर में कोई अंतर नहीं है।
- H2: शिक्षा के आधार पर जागरूकता के स्तर में कोई अंतर नहीं है।
- H3: कार्य अनुभव के आधार पर जागरूकता के स्तर में कोई अंतर नहीं है।

स्टार्ट अप इकोसिस्टम का महत्व

जनवरी 2016 में भारत अभियान की शुरुआत की घोषणा की गई थी। इस पहल का उद्देश्य स्टार्ट-अप व्यवसायों के लिए बैंक वित्तपोषण का समर्थन करके नीति निर्माण में सरकार की भूमिका को कम करना है, जिससे उद्यमिता गतिविधियों में वृद्धि होगी और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। यदि कोई फर्म या इकाई पिछले पाँच वर्षों के दौरान भारत में स्थापित या निगमित की गई है और उसका वार्षिक कारोबार किसी भी पिछले वित्तीय वर्ष में 25 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, तो उसे स्टार्ट-अप के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इसका लक्ष्य तकनीकी रूप से संचालित विकास और विकास, नवाचार और नई प्रक्रियाओं, वस्तुओं और सेवाओं की शुरुआत या व्यावसायीकरण को आगे बढ़ाना होना चाहिए। स्टार्टअप व्यक्ति की खुद की रोजगार क्षमता और दूसरों के लिए रोजगार की संभावनाओं के निर्माण दोनों को सुविधाजनक बनाता है। किसी देश की अर्थव्यवस्था को उसके अधिकांश नागरिकों द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिन्हें या तो काम करना चाहिए या व्यवसाय करना चाहिए। इससे आर्थिक गतिविधि और धन का प्रवाह बढ़ेगा, जो बदले में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है और रोजगार के अवसर पैदा करता है। इसलिए, सफल स्टार्ट-अप

व्यवसाय इस प्रक्रिया में सहायता करते हैं। स्टार्टअप द्वारा अधिक नौकरियां पैदा की जाएंगी। अगले वर्षों में स्टार्टअप द्वारा संभवतः तीन लाख नई नौकरियां पैदा की जाएंगी, क्योंकि 80 प्रतिशत नौकरी चाहने वाले इन कंपनियों के लिए काम करना चुनते हैं, जो पहले से ही निवेश आकर्षित कर रही हैं। मानव संसाधन विशेषज्ञों का अनुमान है कि पिछले वर्ष में ही, स्टार्ट-अप ने 50,000 से 60,000 व्यक्तियों को रोजगार दिया, और निकट भविष्य में सभी उद्योगों के लिए रोजगार का पूर्वानुमान अनुकूल है। मानव संसाधन सलाहकारों के शोध से यह भी पता चला है कि नौकरी चाहने वालों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा - 80% तक - स्थापित व्यवसायों की तुलना में स्टार्ट-अप में नौकरी करना पसंद करते हैं। नई नौकरियों का सृजन स्टार्टअप के प्राथमिक लाभों में से एक है। वैश्विक डेटा के अनुसार, स्टार्टअप हमारे देश में बड़े व्यवसायों की तुलना में अधिक नौकरियां पैदा कर रहे हैं। इंटरनेट, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नवीनतम तकनीक स्टार्टअप द्वारा प्रस्तुत की गई है। आजकल, अधिकांश बड़ी तकनीकी कंपनियाँ अपना काम स्टार्टअप को सौंपती हैं। साथ ही, इससे स्टार्टअप के वित्तीय प्रवाह में सुधार होगा। हालाँकि, किसी भी स्टार्टअप को व्यवसाय में बने रहने के लिए, उन्हें अपने ग्राहकों को गुणवत्ता प्रदान करनी होगी। इस प्रकार, स्टार्टअप हमारे समाज और देशों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि अधिक स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए, हमारे देश को एक उद्यमी संस्कृति विकसित करने की आवश्यकता है। इन युवा उद्यमियों द्वारा छोटे उद्यमों की स्थापना निस्संदेह निकट भविष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी। 2015 के नैसकॉम सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में सालाना लगभग 3100 स्टार्टअप होते हैं, जो इसे अमेरिका, ब्रिटेन और इज़राइल से थोड़ा नीचे रखता है। भारत में 2020 तक 22 से 44 वर्ष की आयु के 112 मिलियन कामकाजी लोग होने का अनुमान है। देश को जनसांख्यिकीय लाभांश से भी लाभ होने की बात कही जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह जनसांख्यिकीय लाभांश देश की स्टार्टअप संस्कृति को मजबूत करेगा। पहले, भारत को भारतीय आईटी सेवाओं और सस्ते श्रम को दुनिया के बाकी हिस्सों में निर्यात करने के लिए एक बाजार माना जाता था। परिणामस्वरूप, भारत में ऐतिहासिक रूप से नवाचार और उत्पाद निर्माण का स्तर खराब रहा है। स्टार्ट-अप वृद्धि का नेतृत्व तकनीकी स्टार्ट-अप कर रहे हैं, जो चालू वित्त वर्ष में आईटी-बीपीएम सुरक्षा राजस्व में लगभग 12-14% की वृद्धि करने के लिए तैयार हैं। इन बाजारों में अपार अप्राप्य क्षमता का लाभ उठाने के लिए, विकसित देश पहले से ही भारत जैसे तेजी से विकासशील और उभरते देशों के लिए आरक्षण कर रहे हैं।

स्टार्ट अप को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सरकारी पहल

1. आसान पंजीकरण: भारत सरकार ने स्टार्ट-अप पंजीकरण की सुविधा के लिए एक वेबसाइट और एक मोबाइल ऐप पेश किया है। स्टार्ट-अप शुरू करने में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति कुछ कागजात अपलोड कर सकता है और एक संक्षिप्त ऑनलाइन फॉर्म भर सकता है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही पूरी की जाती है।

2. लागत बचत: ट्रेडमार्क और पेटेंट में सहायता करने वाली कंपनियों की सूची भी सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है। वे बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित शीर्ष-स्तरीय सेवाएं प्रदान करेंगे, जैसे कि कम लागत पर शीघ्र पेटेंट जांच। स्टार्टअप द्वारा केवल वैधानिक शुल्क वहन किया जाएगा; सभी सुविधा व्यय सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे। उन्हें पेटेंट आवेदन लागत में 80% की कमी का लाभ मिलेगा।

3. फंड तक आसान पहुंच: सरकार ने स्टार्ट-अप को उद्यम वित्तपोषण देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का फंड स्थापित किया है। बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को उद्यम पूंजी प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ऋणदाताओं को गारंटी भी दे रही है।

4. तीन वर्ष का कर-मुक्ति: यदि किसी स्टार्टअप को अंतर-मंत्रालयी बोर्ड (आईएमबी) से प्रमाणन प्राप्त हो जाता है, तो उन्हें तीन वर्षों तक आयकर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

5. टेंडर जमा करें: स्टार्टअप सरकार को टेंडर जमा कर सकते हैं। वे "पूर्व अनुभव / टर्नओवर" की आवश्यकताओं के अधीन नहीं हैं जो सरकारी टेंडरों का जवाब देने वाले नियमित व्यवसायों पर लागू होती हैं।

6. अनुसंधान एवं विकास सुविधाएं: अनुसंधान एवं विकास उद्योग में उद्यमियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क, आईआईटी मद्रास अनुसंधान पार्क, आईआईटी हैदराबाद अनुसंधान पार्क और आईआईटी भुवनेश्वर अनुसंधान एवं उद्यमिता पार्क जैसे अनुसंधान पार्क स्थापित किए गए हैं।

7. समय लेने वाली अनुपालन प्रक्रिया नहीं: स्टार्ट-अप के पैसे और समय की बचत के लिए, कई अनुपालन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया गया है।

8. निवेशकों के लिए कर बचत: जो निवेशक अपने पूंजीगत लाभ को सरकार द्वारा स्थापित उद्यम निधि में लगाते हैं, उन्हें पूंजीगत लाभ कर से छूट मिलती है। इससे स्टार्टअप को अतिरिक्त धन प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

9. सरल निकास: किसी स्टार्टअप के पास समापन के लिए आवेदन की तिथि से 90 दिनों के भीतर अपना परिचालन बंद करने का समय होता है।

10. अन्य व्यवसाय मालिकों के साथ नेटवर्क: स्टार्टअप के कई हितधारकों के बीच बैठकों की सुविधा के लिए, सरकार ने प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो स्टार्टअप उत्सव आयोजित

करने का सुझाव दिया है। इससे नेटवर्किंग के ढेरों अवसर मिलेंगे। सरकार स्टार्टअप को बहुत प्रोत्साहन देती है।

तालिका 1: स्टार्ट-अप इंडिया के अंतर्गत विभिन्न सरकारी योजनाओं का अर्थ

सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएँ	चाबीक्षेत्र	राजकोषीयसरकार द्वारा प्रोत्साहन
सहायताके लिएअंतरराष्ट्रीयपेटेंटइलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स में संरक्षणजानकारीतकनीकी	एमएसएमई-आईटीसीक्षेत्र	जोड़कुलकारुपये15.0लाखोंप्रतिआविष्कारया50%का कुलखर्च
गुणकअनुदानयोजना	आर&डीउद्योगऔरशैक्षणिक	एअधिकतमकाभारतीय रुपया2करोड़प्रतिपरियोजना
सॉफ्टवेयरतकनीकीपार्कयोजना	सॉफ्टवेयर निर्यातऔरसॉफ्टवेयरकंपनियों	डीटीएऊपरको50%काएफओबीकीमतकानिर्यात
इलेक्ट्रॉनिकविकासनिधि(ईडीएफ)नीति	इलेक्ट्रॉनिक्सप्रणालीडिज़ाइनऔरउत्पादनक्षेत्र	भिन्नमामलाकोमामला
संशोधितविशेषप्रोत्साहनपैकेट योजना(एम-एसआईपीएस)	इलेक्ट्रॉनिकऔरयहक्षेत्र।	1.20%के लिएसेज 2,25%के लिएगैर सेज
योजनाकोसहायतामें जनसंपर्कजागरूकताई एंड आईटी पर सेमिनार/कार्यशालाएंक्षेत्र	(बौद्धिकसंपत्ति)जागरूकता	1.शिक्षात्मकसंस्थान का-2लाख 2.उद्योगनिकायोंपसंदएमआईटी,एल्सीना,फिक्की,वगैरह -3लाख 3.मैतीसमाज/स्वायत्तशरीर-5लाख
न्यू जेन इनोवेशन और उद्यमिता विकास केंद्र	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शैक्षणिक संस्थान	अधिकतम 25 लाख रुपये
उद्यम पूंजी सहायता योजना	बैंकिंग (ऋण)	1. प्रमोटर की इक्विटी का 26% और 50 लाख रुपये (पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में स्थित परियोजनाएं) 2. प्रमोटर की इक्विटी का 40% और 50 लाख रुपये (जहां परियोजना को किसान उत्पादक संगठन के तहत बढ़ावा दिया जाता है)
क्रेडिट गारंटी	एमएसई सेक्टर	50 लाख रुपये तक 75% ऋण सुविधा
प्रदर्शन और क्रेडिट रेटिंग योजना	लघु उद्योग.	अधिकतम 50 लाख, / रेटिंग शुल्क का 75% / 25,000 रुपये (जो भी कम हो)

कच्चे माल की सहायता	कच्चे माल के लिए एमएसएमई को वित्तपोषण	9.5-10.5% (270 दिन) अन्यथा, 10-11%
पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि की संशोधित योजना (एसएफयूआरटीआई)	पारंपरिक उद्योग और कारीगर	8 करोड़ रुपये/क्लस्टर (विरासत क्लस्टर) 3 करोड़ रुपये/क्लस्टर (प्रमुख क्लस्टर) 1 करोड़ रुपये/क्लस्टर (मिनी क्लस्टर)
एकल बिंदु पंजीकरण योजना	एमएसई सेक्टर	बयाना राशि जमा और निविदा शुल्क से छूट दी गई है
नवाचार, उद्यमिता और कृषि -उद्योग को बढ़ावा देने के लिए योजना	ग्रामीण एवं कृषि आधारित उद्योग	प्लांट एवं मशीनरी की लागत का 1.50% / अधिकतम 30 लाख रुपये (मौजूदा इन्क्यूबेशन सेंटर) प्लांट एवं मशीनरी की लागत का 2.50% / अधिकतम 100 लाख रुपये (नए इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए) 3. इनक्यूबेटर्स के लिए 10 कार्यशालाएं आयोजित करने हेतु एक्सेलरेटर्स के लिए 200 लाख रुपये, बीज पूंजी के रूप में 1 करोड़ रुपये का एकमुश्त अनुदान
बुनियादी ढांचा विकास योजना	एमएसएमई (कार्यालय स्थान)	पट्टे पर किराये के आधार पर कार्यालय स्थान
एमएसएमई बाज़ार विकास सहायता	लघु/सूक्ष्म विनिर्माण उद्योग (निर्यात)	सूक्ष्म एवं लघु विनिर्माण उद्यमों (अनारक्षित श्रेणी) के लिए इकोनॉमी क्लास द्वारा हवाई किराये का 1.75% तथा स्थान किराया शुल्क का 50% 2.100% स्थान, किराया और इकोनॉमी क्लास हवाई किराया (महिलाएं / एससी/एसटी उद्यमी)
राष्ट्रीय पुरस्कार (व्यक्तिगत एमएसई)	एमएसएमई (राष्ट्रीय पुरस्कार)	रैंकिंग के अनुसार 1 लाख, 75000 और 50000 रुपये
अटलसंवर्धनप्रयोगशालाओं	शिक्षाक्षेत्र	भारतीय रुपया12लाखोंप्रत्येक
स्केल अपसहायताकोकीस्थापनाइन्क्यूबेशनकेन्द्रों	इन्क्यूबेशनकेन्द्रों	भारतीय रुपया10करोड़मेंदोवार्षिककिश्तोंकाभारतीय रुपया5करोड़प्रत्येक
उड़ानप्रशिक्षणबेरोजगार युवाओं के लिए कार्यक्रमकाजम्मू और कश्मीर	रोज़गार	उपलब्ध करवानारोजगार उन्मुखप्रशिक्षणकोयुवाकाजम्मू और कश्मीर

Viksit Bharat

2024 | Volume: 01 | Issue: 01|

वृद्धिकाप्रतिस्पर्धामें भारतीय पूंजी चीजें क्षेत्र	औद्योगिक	25% कालागत का तकनीकी अधिग्रहण (अधिकतम 10 करोड़)
राष्ट्रीय साफ ऊर्जा निधि पुनर्वित्त	लघु जल विद्युत (एसएचपी) परियोजनाओं	अधिकतम 30% का ऋण असाधारण, @ 2% ROI (कम बजाय 15 करोड़)
इरेडा योजना छूट ऊर्जा विधेयकों	अक्षय ऊर्जा	ऊपर को 75% का चालान कीमत लंबित के लिए अधिकतम छह महीने (अधिकतम 20 करोड़)
पुल ऋण खिलाफ एमएनआरई पूंजी सस्मिडी	अक्षय ऊर्जा	न्यूनतम 20 लाख रुपये
पुल ऋण खिलाफ पीढ़ी-आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) दावा	सौर शक्ति परियोजनाओं	न्यूनतम 20 लाख रुपये
ऋण के लिए छूट सौर पीवी शक्ति परियोजनाओं	सौर शक्ति परियोजनाओं	70% का परियोजना लागत + 30% प्रमोटरों योगदान
श्रेय वृद्धि गारंटी योजना	अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं	गारंटी ऊपर को 25% का प्रस्तावित मुद्दा आकार का बॉन
डेरी उद्यमशीलता विकास योजना	असंगठित क्षेत्र	25% का परिव्यय (सामान्य) 33.33% (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/किसान)
4ई (अंत को अंत ऊर्जा क्षमता)	एमएसएमई	90% का परियोजना लागत परिवर्तनीय बी/डब्ल्यू 10 लाख से 150 लाख.
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)	विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र	ऋण तक भारतीय रुपया 10 लाखों
खड़ा होना ऊपर भारत	ग्रीनफील्ड उद्यम	ऋण बीच में भारतीय रुपया 10 लाखों और भारतीय रुपया 1 करोड़ (एससी/एसटी/औरत उद्यमी)

सतत वित्त योजना	एमएसएमई (टिकाऊ) विकास)	सहायता है प्रदान किया द्वारा रास्ता का अवधि क्रम
सिडबी मेक इन इंडिया सॉफ्ट लोन निधि के लिए माइक्रो छोटा और मध्यम उद्यम (मुस्कान)	एमएसएमई	1.10% का परियोजना लागत (अधिकतम 20 लाख) यूआर 2.15% का परियोजना लागत (अधिकतम 30 लाख) (एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी)
शुरू ऊपर सहायता योजना	तकनीकी सेवा	भारतीय रुपया 200 लाखों (अधिकतम)
विकास पूंजी और हिस्सेदारी सहायता	एमएसएमई	सिडबी प्रदान आसान क्रम
सहायता को पेशेवर निकायों और सेमिनार/ संगोष्ठी	शिक्षा क्षेत्र	यात्रा सहायता को वैज्ञानिक
आयुर्वेदिक जीव विज्ञान कार्यक्रम	आयुर्वेद	नाम मात्र सहायता के लिए पूर्व ऑपरेटिव खर्च पसंद घोषणा एंजोशर.
उद्योग उपयुक्त अनुसंधान एवं विकास	औद्योगिक	अनुदान के लिए परियोजना संबंधित लागत
उच्च जोखिम उच्च इनाम अनुसंधान	विज्ञान और तकनीकी	अनुदान के लिए परियोजना संबंधित लागत
तकनीकी विकास कार्यक्रम (टीडीपी)	विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास	ऊपर को 50% का लागत का उपभोग है प्रदान किया।

"स्टार्टअप्स के लिए भारतीय पारिस्थितिकी सरकारी योजनाएं"

राष्ट्रीय विज्ञान और तकनीकी प्रबंधनकारी प्रणाली (एनएसटीएमआईएस)	अनुसंधान परियोजनाओं	1. 10% का कुल परियोजना लागत के लिए शिक्षात्मक संस्थान और गैर सरकारी संगठनों 2. 8% के लिए प्रयोगशालाएं और संस्थान अंतर्गत केंद्रीय सरकार विभाग/एजेंसियां
जैव प्रौद्योगिकी उद्योग साझेदारी कार्यक्रम (बीआईपीपी)	विज्ञान और तकनीकी	सहायता के लिए तकनीकी विकास
उद्योग नवाचार कार्यक्रम पर चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक्स (आईआईपीएमई)	इलेक्ट्रॉनिक्स और जानकारी तकनीकी	1. भारतीय रुपया 50 लाखों (18 महीने) और भारतीय रुपया 100 लाखों (24 महीने) (प्रारंभिक लेन देन) 2. ऋण के लिए 24 महीने (संक्रमण को पैमाना)।
अतिरिक्त दीवार अनुसंधान अनुदान	अनुसंधान परियोजनाओं	35 लाख-3 वर्ष
स्पर्श (सामाजिक नवाचार) उत्पादों के लिए कार्यक्रम: खरीदने की सामर्थ्य और उपयुक्त को सामाजिक स्वास्थ्य)	जैव प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य देखभाल	1. रु 50 लाख (18 महीने). 2. रु. 50 लाख (24 महीने) 3. अभिनव पायलट पैमाना वितरण मॉडल-24 महीने
नवाचारों को बढ़ावा देना व्यक्ति, क्षेत्र की नई कंपनियों और एमएसएमई (प्रिज्म)	वैज्ञानिक और औद्योगिक इकाइयों	1. ए अधिकतम का भारतीय रुपया 2 लाखों या 90% का कुल परियोजना लागत (जो भी हो है कम) 2. भारतीय रुपया 5 लाखों को भारतीय रुपया 35 लाख, ए अधिकतम का भारतीय रुपया 20 लाखों या 90% का कुल परियोजना लागत (जो भी हो है कम) 3. भारतीय रुपया 35 लाखों को भारतीय रुपया 100 लाख, ऊपर को भारतीय रुपया 50 लाख सीमित को 50% का कुल परियोजना लागत 4. अधिकतम रुपये 50 लाखों सीमित को 50% का कुल परियोजना लागत
विज्ञान और तकनीकी का योग और ध्यान	योग और ध्यान	सीमित को तीन साल
तेज़ अनुदान के लिए युवा अन्वेषक	जैव प्रौद्योगिकी	अनुदान के लिए अनुसंधान में जैव प्रौद्योगिकी
जैव प्रौद्योगिकी इन्प्रिशन अनुदान	जैव प्रौद्योगिकी	अधिकतम रुपये 50 लाखों (18 महीने)

स्रोत:

<https://www.startupindia.gov.in/content/sih/en/government-schemes.htm>

तालिका 2: जनसांख्यिकीय विवरण के संबंध में जागरूकता का स्तर

		स्तरकाजागरूकता			कुल	ची-स्कायर	पी-मूल्य
		नहींपरसभीजागरूक	थोड़ाजागरूक	कुछ हद तकजागरूक			
आयु	20-25	23	17	5	45	5.247	.513
		51.1%	37.7%	11.1%	100.0%		
	25-30	10	12	7	29		
		34.4%	41.3%	24.1%	100.0%		
	30-35	5	7	1	१३		
		38.6%	53.8%	7.6%	100.0%		
	>35	8	4	1	१३		
		61.5%	30.7%	7.6%	100.0%		
कुल		46	40	14			

लिंग	पुरुष	25	33	10	68	4.6	.100
		36.7%	48.5%	14.7%	100.0%		
	महिला	15	9	8	32		
		46.8%	28.1%	25%	100.0%		
कुल		40	42	18			
शिक्षा	अंतर्गतस्नातक	9	5	2	16	14.44	.006
		56.2%	31.2%	12.5%	100.0%		
	स्नातक	20	22	7	49		
		40.8%	44.8%	14.2%	100.0%		
	डाकस्नातकऔरडॉक्टर की उपाधि	15	12	8	35		
		42.8%	34.2%	22.8%	100.0%		
कुल		44	39	17	100		
कामअनुभव	1 से कमसाल	8	15	3	26	10.27	.114
		30.7%	57.6%	11.5%	100.0%		
	1-2साल	9	१३	7	29		
		31%	44.8%	24.1%	100.0%		
	3-4साल	14	9	5	28		
		50%	32.1%	17.8%	100.0%		
	5 से ऊपरसाल	11	5	1	17		
		64.7%	29.5%	5.8%	100.0%		
कुल		42	42	16	100		
					100.0%		

निष्कर्ष और परिणाम

स्टार्ट-अप इंडिया के तहत सरकारी योजनाओं के बारे में उद्यमियों के बीच जागरूकता के स्तर को मापने के लिए, इसे निर्धारित करने के लिए ची स्कायर विश्लेषण का उपयोग किया

गया था। सर्वेक्षण उत्तरदाताओं की जनसांख्यिकीय प्रोफाइल तालिका 2 में संक्षेपित है। सारांश सांख्यिकी का अवलोकन स्टार्ट-अप इंडिया अभियान के हिस्से के रूप में शुरू किए गए सरकारी कार्यक्रमों के बारे में जनता के ज्ञान में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। कारक "आयु" के लिए, p मान 0.05 से अधिक है।

नतीजतन, शून्य परिकल्पना (H0) को गलत साबित कर दिया गया है। नतीजतन, आयु समूहों में उद्यमियों के जागरूकता स्तरों में कोई सराहनीय अंतर नहीं है। कारक "लिंग" के लिए, p मान 0.05 से कम है। नतीजतन, अध्ययन शून्य परिकल्पना को गलत साबित करने में असमर्थ था। नतीजतन, पुरुष और महिला उद्यमियों के जागरूकता स्तर में काफी भिन्नता है। कारक "शिक्षा" के लिए, p -मान 0.05 से कम है। परिणामस्वरूप, अलग-अलग शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाले उद्यमियों के जागरूकता स्तरों में उल्लेखनीय अंतर हैं। कारक "कार्य अनुभव" के लिए, p -मान 0.05 से कम है। परिणामस्वरूप, शून्य परिकल्पना (H3) स्वीकार की जाती है। व्यावसायिक अनुभव की अलग-अलग डिग्री वाले उद्यमियों के जागरूकता स्तरों में उल्लेखनीय अंतर हैं।

तालिका 3: सरकारी योजनाओं के उपयोग का भारत औसत

प्रयोग	हाँ	नहीं
नहीं।काउद्यमियों	6%	94%

भारत औसत विश्लेषण का उपयोग करने पर यह पाया गया किलुधियाना में केवल 6% उद्यमियों ने उठाया लाभस्टार्ट-अप इंडिया के तहत विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी अभियान।

निष्कर्ष और सिफारिश

एक विचार किसी व्यवसाय को शुरू करने में पहला कदम होता है, लेकिन एक विचार को कंपनी में विकसित करने के लिए, मार्गदर्शन, फंडिंग, टीमवर्क, बाजार व्यवहार्यता, कानूनी आवश्यकताएं आदि सभी आवश्यक हैं। एक उद्यमी के दृष्टिकोण से, वित्तीय बाधाएँ सबसे महत्वपूर्ण हैं और उन्हें अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। कम लागत वाली फंडिंग उपलब्धता और सरल प्रसंस्करण व्यवसाय शुरू करने या बढ़ाने के लिए दो ऐसे लाभ हैं। विभिन्न कार्यक्रमों और प्रोत्साहनों के माध्यम से, भारत सरकार ने अधिक स्टार्ट-अप व्यवसायों के लिए बाजार में प्रवेश करने और नए व्यवसाय स्थापित करने या पहले से मौजूद व्यवसाय को संभालने के लिए परिस्थितियाँ बनाई हैं। लेकिन अभी भी वर्तमान में, लोग सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में जागरूक नहीं हैं, इसलिए सरकार की ओर से आम आदमी तक पहुँचने और उन्हें विभिन्न सरकारी पहलों के बारे में विस्तार से बताने के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। इसे स्कूल और कॉलेज/विश्वविद्यालय स्तर पर शुरू किया जा

सकता है, जिसमें विभिन्न राज्य, शहर, जिले और कस्बे भी शामिल हैं। प्रिंट मीडिया, रेडियो, टीवी अभियान और सोशल मीडिया नेटवर्किंग के माध्यम से अधिक प्रचार-प्रसार को अपनाया जाना चाहिए।

संदर्भ

- Agarwal. M. (2017), '50+ Start-up Schemes by The Indian Government That Start-ups Should Know About. Department of Industrial policy and promotion, Government of India.
- Audretsch, D. B., & Acs, Z. J. (1994). New-firm startups, technology, and macroeconomic fluctuations. *Small Business Economics*, 6(6), 439-449
- Ávila, L. V., Leal Filho, W., Brandli, L., Macgregor, C. J., Molthan-Hill, P., Özuyar, P. G., & Moreira, R.
- Berna, J.J. (1960) *Industrial Entrepreneurship in Madras State*, Asia Publishing House. Bombay, p.6.
- Butler, I., Galassi, G. And Ruffo, H.(2016) "Public Funding for Startups in Argentina: An Impact Evaluation". *Small Business Economics* 46, No. 2, pp. 295-309.
- Casanova, L., Klaus, P.C. and Dutta, S. (2017) *Financing Entrepreneurship and Innovation in Emerging Market* Elsevier Academic Press.
- Changhong, Li., Yulin, S., Cong, W., Zhenyu, W. and Li, Z. (2016) "Policies of Promoting Entrepreneurship and Angel Investment: Evidence from China". *Emerging Markets Review* 29, pp. 154-167.
- Deshapande, M.U. (1989) *Entrepreneurship of Small Scale Industry - Concept, Growth and Management*. Deep and Deep Publications, Delhi, 1989.
- Gavin C. (2004) "The Financing of Business Start-Ups". *Journal of Business Venturing* 19, pp. 261-283.
- Guan and Yam (2015) "Effects of Government Financial Intention of Firm's Innovation Performance in China : Evidences from Beijing in 1990s". *Research Policy* 44 , No. 1, pp. 273-28.
- Jain, Nirupa & Jain T.K. (2018). *Defining Ecosystems for Startups and Entrepreneurship: Decoding Characteristics of Entrepreneurs*, Kindle edition.
- Jain, Nirupa and Jain T.K. (2018). *Developing Institutions through Volunteering for Diversity: Creating a better Society*, Kindle Edition.

- Jain, Trilok Kumar (2018), *The Road From Entrepreneurship to Social Entrepreneurship: The Journey and the Challenges* (November 15, 2018). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3284984> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3284984>
- Jain, Trilok Kumar(2018), *Entrepreneurial Training and Startup Initiative Among Students: The Case of Suresh Gyan Vihar University Jaipur* (November 29, 2018). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3292801>
- Jain, Trilok Kumar(2018), *Institution Building Through Effective Academic Performance Indicators and Mentoring* (November 15, 2018). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3285103> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3285103>
- Jain, Trilok Kumar(2018), *Social Entrepreneurship: Indian Roots* (February 22, 2018). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3284943> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3284943>
- Jain, Trilok Kumar(2018), *Towards the Theory of Green Entrepreneurship* (November 15, 2018). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3284935> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3284935>
- Jain, Trilok Kumar(2018), *The Cox Leadership in Academics: A Case Study on University Administration and Institution Building by Inspiring*
- Leal Filho, W. (2000). *Dealing with misconceptions on the concept of sustainability. International journal of sustainability in higher education*, 1(1), 9-19.
- Leal Filho, W., & Brandli, L. (2016). *Engaging stakeholders for sustainable development. In Engaging Stakeholders in Education for Sustainable Development at University Level* (pp. 335-342). Springer, Cham.
- M. (2017). *Barriers to innovation and sustainability at universities around the world. Journal of cleaner production*, 164, 1268-1278.
- *Multiple Rovers* (December 22, 2018). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3305637>
- Pasquier, M. (2015), 'The State of India startup ecosystem: here comes the growth' (and 10,000 start-ups)
- Pathak H.N. (1972) "Small Scale Industries in Ludhiana". *Economics and Political Weekly* 7, No.48,
- Pillai, K.Q. (1989) *Women Entrepreneurship in a Industrial Backward State*. Cited in N.S. Bisht and others (Ed.), *Entrepreneurship - Reflections and Investigations*, Chugh Publications, Allahabad.
- Pugliese, P. (2001). *Organic farming and sustainable rural development: A multifaceted and promising convergence. Sociologia ruralis*, 41(1), 112-130.
- Ralph, M., & Stubbs, W. (2014). *Integrating environmental sustainability into universities. Higher Education*, 67(1), 71-90.
- Rao V. L. (1986) *Industrial Entrepreneurship in India*. Chugh Publications, Ahmedabad, pp. 95-100.
- Swamidass, P. M. (2013). *University startups as a commercialization alternative: lessons from three contrasting case studies. The Journal of Technology Transfer*, 38(6), 788-808
- Tilbury, D. (2004). *Environmental education for sustainability: A force for change in higher education. In Higher education and the challenge of sustainability* (pp. 97-112). Springer, Dordrecht.
- Vehmaa A, Karvinen M, Keskinen M. (2018). *Building a More Sustainable Society? A Case Study on the Role of Sustainable Development in the Education and Early Career of Water and Environmental Engineers. Sustainability*; 10(8):2605.
- Von Gelderen, M., Frese, M., & Thurik, R. (2000). *Strategies, uncertainty and performance of small business startups. Small Business Economics*, 15(3), 165-181
- Wiek, A., Bernstein, M., Foley, R., Cohen, M., Forrest, N., Kuzdas, C., ... & Withycombe Keeler, L. (2015). *Operationalising competencies in higher education for sustainable development. Handbook of higher education for sustainable development. Routledge*, 241-260.
- Zhijun, F., & Nailing, Y. (2007). *Putting a circular economy into practice in China. Sustainability Science*, 2(1), 95-101
- Saradadevi K., (1989) "Entrepreneurship of Women in India", *Khadi Gramodyog* 35, No.6, pp.269-271.
- Singh, B.N. (1964) "Pattern of Entrepreneurship in Agra - With Special Reference to Light Engineering Industry". *Indian Journal of Commerce* 17, No.60, pp.205-213.
- Times of India report, "17 startups to watch in 2017" <https://timesofindia.indiatimes.com/companies/17-startups-to-watch-in-2017/article-show/56271459.cms>. Accessed on 21.02.18